मूल्य एक प्रति 3.00 रु.
Registered with the Registrar of News Paper (Govt. of India) Vide R.N.I. No. 39299/81 — On The Way Half Century 50 — Monday & Tuesday every week on Delhi Postal Regd. No. DL(E)-20/5174/2021-23

व्यापार एक्सप्रेस
(हिन्दी साप्ताहिक)

Office : 2718, Street No. 5, Bihari Colony, Shahdara, Delhi-110032
Mob.: +91-9312625326, 9717513928
Email: vyaparexpress50@gmail.com, vyaparexpress@ymail.com
CHIEF EDITOR : T.R. ARORA
www.vyaparexpress.co

वर्ष 42 अंक 05 • 07 फरवरी 2022 — 13 फरवरी 2022 प्रकाशन की तिथि हर सोमवार वार्षिक मूल्य सप्लीमेंट्री सहित 1100/— पृष्ठ—4

किसानों को बजट में क्या मिला, जानिए

सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। साथ ही, बुंदेलखंड के लिए केन–बेतवा नदी परियोजना के लिए भी 44605 करोड़ रुपये का आंवटन किया है।

कषि सेक्टर की अहम बातें।

साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021–22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना।

एसपी मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया जाएगा। रसायनिक उवरकों पर निर्भरता को कम किया जाएगा। साथ ही, कृषि क्षेत्र में पोषणयुक्त खेती के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

राज्यों को विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। इससे छात्र आधुनिक और जीरो बजट खेती के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे।

2021–22 में 1,000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी। जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

केन–बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया। इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर रकबे को सिंचाई का पानी प्राप्त होगा।

किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई को साथ में लेकर व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा।

तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना चलाई जाएगी।

गंगा कॉरीडार के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है।

किसानों को डिजिटल और हाई–टेक सेवाएं प्रंदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की होगी शुरुआत।

प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।

बजट में किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का ऐलान, केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य

निर्मला सीतीरमण
वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्रों के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने बताया कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। साथ ही, आगामी वर्ष में केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

संसद में बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खारीदारी की जाएगी। गेहूं और धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा। साथ ही, एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधा किसानों के खातों में किया जाएगा।

देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के पांच किलोमीटर के चौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनका कहना है कि, पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान विस्तार संस्थानों के साथ–साथ निजी एग्रोटेक प्लेयर शामिल होंगे।

कृषि फसलों का आंकलन, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे अपने कृषि विश्व–विद्यालयों को प्रोत्साहित कर सकें।

वित्त मंत्री ने बताया कि 44 हजार 605 करोड़ की अनुमानित लागत से केन बेतवा परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना को देश के 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई उपलब्ध करवाना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना आदि है। इन परियोजनाओं के लिए अनुमान 2021–22 में 4300 करोड़ रुपये और 2022–23 1400 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया है।

कृषि सेक्टर के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1,000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा।

कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर पार की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष 2021–22 में भारत का कृषि निर्यात के इतिहास में पहली बार 50 अरब डॉलर के स्तर को पार कर जाने की उम्मीद है। यद्यपि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल–दिसम्बर के तहत भारत के कृषि का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 23.21 प्रतिशत बढकर 31.05 अरब डॉलर के स्तर को छू चुका है और अगले आंकड़े आने पर भारत का कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर के रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढेगा।

दरअसल कोरोना के बाद हाल ही में निर्यात बढाने को लेकर केद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदम का परिणाम परिलक्षित हो रहा है। जिसके तहत केद्र सरकार ने सर्टिफिकेशन के नए तरीकों का प्रयोग शुरु किया है।

इन उपायों में विभिन्न प्रमाण पत्रों व मान्यताओं की वैधता की समाप्ति अवधि के बाद उनकी वैधता का विस्तार करना शामिल है।

केद्र सरकार ने चीनी निर्यात की समस्याओं के समाधान करने के लिए कंट्रोल रुम स्थापित किए है। वहीं नए परीक्षण केद्रों की स्थापना को सरल बनाया है।

भारत रत्न' से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर का निधन, शोक में डूबा देश

अपनी सुरीली आवाज से देश–दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर–साम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया है। वह 92 वर्ष की थीं। 'भारत की नाइटिंगेल' के नाम से दुनियाभर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब पांच दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एकछत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

दिग्गज हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

लता के निधन पर भारत समेत दुनियाभर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता के साथ कई तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, 'दयालु और सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़ गई हैं। वह हमारे देश में ऐसी शून्यता छोड़ गई हैं जो कभी भर नहीं सकेगी।' केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, 'उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती रही हैं। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है।

सेना के जवान लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर घर से बाहर लाए। इसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के ट्रक में रखाकर शिवाजी पार्क ले जाया गया। मुंबई के हजारों लोग लता ताई को अंतिम विदाई देने सड़कों पर उतर आए। लता जी की पार्थिव देह दोपहर 1.10 बजे बीच कैंडी अस्पताल से उनके घर पहुंची थी।

क्षेत्रीय मंडियों के बाजार भाव

कानपुरः गेहूं लूज 2150/2155, जौ 1975/2000, चावल मसूरी 2450/2550, चावल मोटा 2250/2400, देशी चना 5300/5325, चना छना 5850/5950, दाल चना 5900/6000, पिचकी 4800/5000, मटर दाल 7200/7400, अरहर लेमन 6600/6625, दाल अरहर 8900/9300, स्पेशल 8100/8400, उड़द एसक्यू 7250/7260, एफएक्यू 6600/6650, राजमा चित्रा 9900/13100, मूंग 5700/6500, मसूर छोटी 7600/7750, छांटी 8800/9300, सरसों 7300/7350, तिल सफेद 10000/10100 सोया (टीन) 2200/2250, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 2550/2600, सरसो खल 3300/3350, पामोलिन 2150/2200, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1850/1950, मधुसूदन देशी घी 6200 वासुदेव 5950, परम प्रीमियम 6250 अलसी 9500/9700, धानियाः लोकल 9700/9800, राजस्थान 102000/10400

लखनऊः गेहूं दड़ा 2130/2140, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 4000/4050, स्टीम 5050/5150, लालमती 4400/3500, चावल (सोना) 4200/4300, दाल अरहर सवा नं. 7800/7900, पटका 8700/9300 रिजैक्शन 6700/7000, चना दाल 5950/6100, चना देशी छना 5950/6100, चना चापा छना 5900/6000, मटर विदेशी 7400/7500, उड़द साबुत (काला) 7200/8000, दाल उड़द (काली) 7900/8900, उड़द धोया 8000/8800, मसूर छोटी 7500/7700, मलका 8500/8800, किरानाः जीरा 18400/19800 लालमिर्च गुंटूर 17500/2300, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 5600/5700, धनिया एमपी 10100/12200, छोटी इलायची (किलो) 1000/1500, बडी इलायची 710/740, कालीमिर्च (किलो) 520/580, सुपारी (किलो) 580/630, सौंफ मोटी 9400/11800, मंगरैल 22500/23500, चिरौंजी (किलो) 1125/1250, मखाना 475/700

मुजफ्फरनगरः चाकू (कोल्ड) 1140/1270, खतौली 3540, देवबंद 3400, थाना भवन 3410, बुढ़ाना 3420, शामली 3390, चीनी हाजिर 3750/3850

हापुड़ः अनाज–दाल गेहूं 2215/2220, चावल परमल 2400/2450, डुप्लीकेट बासमती सेला 6100/6200, बासमती 1121 स्टीम 7400/7500, चना 5200/5250, चनादाल 5800/5900, काबली चना 7000/8500, राजमा देशी चित्रा 11500/13000, दाल अरहर 8000/8800, मसूर 7800/8000, उड़द देसी 6500/6700, दाल उड़द 7500/8500, मूंग यूपी 6500/6800, मूंग दाल 8000/9000, गुड़–चीनीः चीनी हाजिर 3800/3900

चीनी मिलों द्वारा केद्र सरकार के फैसले का पुरजोर स्वागत

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) की तरफ से पहली अक्टूबर से गैर मिश्रित ईंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने को लेकर केद्र सरकार के फैसले से एथलॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को बढावा मिलेगा। ऐसे में इस्मा की तरफ से केद्र सरकार के इस फैसले का पूरजोर स्वागत किया गया है। दरअसल केंद्रीय राजस्व विभाग की तरफ से पहली फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना के तहत मिश्रित (एथलॉल व मेथनॉल के साथ) के रुप में वर्गीकृत किए जाने वाले ईंधन को बीआईएस विनिर्देशों के अनुरुप होना चाहिए। जिसको लेकर इस्मा की तरफ से कहा गया है कि तेल निर्माण कंपनियों (ओएमसी) से वास्तविक उठान मिश्रित ईंधन प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए सुधार करेगा जो कि वर्तमान में लगभग 10 प्रतिशत है और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से बचाने के लिए है। वहीं एथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए केद्र सरकार ने चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए 2021–22 के संशोधित अनुमान में 160 करोड़ रुपए और 2022–23 के बजट अनुमान में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जिससे एथलॉल उत्पादन क्षमता में वृद्वि होगी व देश में अधिक एथलॉल डिस्टिलरीज की स्थापना को बढावा मिलेगा। जिसको लेकर इस्मा की तरफ से कहा गया है कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमएस) ने ईओआई का चौथा चक्र जारी किया है। जिसमें एथनॉल सीजन 2021–22 के तहत खरीद के लिए लगभग 95 करोड़ लीटर एथनॉल की आवश्यकता का संकेत दिया गया है। यह इंगित करता है कि मात्रा की गणना 11 प्रतिशत सम्मिश्रण पर विचार करके की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान ने चीनी उद्योग के लिए बजटीय आवंटन में मूल बजट अनुमान (लगभग 4337 करोड़ रुपए से 6844 करोड़ रुपए तक) की तुलना में लगभग 2507 करोड़ रुपए की वृद्वि की है। ऐसे में मुख्य रुप से चीनी मिलों के दावों को निपटाने के लिए चीनी मिलों को 2019–20 के लिए सहायता और 2020–21 चीनी सीजन के लिए निर्यात सहायता की योजना के तहत है।

बारिश से गेहूं और सरसो की खडी फसल को नुकसान

उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्वी जिलों में हुई बेमौसम बारिश और ओलों नें खेती की दशा व दिशा बिगाड़ दी है। गेहूं और सरसो की खड़ी फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है तो आलू की पछैती की फसल प्रभावित हुई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बीते सप्ताह 3 दिनों तक जबरदस्त बारिश और ओले गिरे हैं जो किसानों के लिए आफत बन कर आया है। तेज आंधी के साथ गिरे ओलों के चलते खेतों में खासी बढ़ चुकी गेहूं की फसल जमींदोज हो गयी वहीं सरसों से पके फूल टूट गए हैं। आलू की अगैती की फसल बाजार में आ चुकी है मगर बड़ी तादाद में देर में बोने वाली फसल खेतों में ही खराब हो गयी है।

प्रदेश में इस बार कई बार की बारिश के बाद भी आलू की अच्छी फसल की उम्मीद जताई जा रही थी। अगैती आलू की फसल प्रदेश में शिकोहाबाद, फिरोजबाद, अलीगढ़, हाथरस और आगरा व इटावा में बाजार में भी आ चुकी थी। हालांकि बड़ी तादाद में आलू की फसल अभी खेतों में ही है जहां क्यारियों में पानी भर गया है। सूत्रों के अनुसार, इस बार प्रदेश में आलू की पैदावार 160 लाख टन तक होने की उम्मीद थी, हालांकि अगैती की फसल को जाड़े की शुरुआती बारिश में नुकसान हो गया था। किसानों ने एक बार नुकसान उठाने के बाद लेट वैरायटी की फसल बोकर नुकसना को पूरा कर लिया था। बीते सप्ताह और एक महीने में दूसरी बार हुयी जोरदार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है।

जनवरी में हुई बारिश ने जहां गेहूं की फसल को सिंचाई का फायदा पहुंचाया था वहीं इस बार ओलों के साथ आए आंधी पानी ने इसे नुकसान पहुंचाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की खड़ी फसल खेतों में गिर गई है।

गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च के बाद आगे बढ़ाए जाने के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया। केंद्र ने मार्च, 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने को लेकर योजना शुरू की थी। इसका मकसद महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की कठिनाइयों को कम करना था। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता है। यह एनएफएसए के तहत 2–3 रुपए किलो की दर से सामान्य खाद्यान्न आवंटन के अलावा है। सीतारमण ने बजट बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मुझे बजट में कही गई बातों के अलावा कुछ नहीं कहना है।" उनसे यह पूछा गया था कि क्या पीएमजीकेएवाई का दायरा मार्च, 2022 के बाद बढ़ाया जाएगा। पीएमजीकेएवाई योजना 2020–21 में केवल तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर जुलाई–नवंबर कर दिया।

कोविड संकट बने रहने पर इसे 2021 में मई और जून में फिर लागू किया गया और चौथे चरण के तहत पांच महीने के लिए जुलाई से नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया।

किसानों ने बेहतर रिटर्न के लिए रोका कपास का स्टाक

भारतीय कपास की कीमतें अगले कुछ महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब स्थिर होने की संभावना है क्योंकि किसान बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए अपनी उपज को रोकना पसंद कर रहे हैं। राजकोट के कारोबारी एक का कहना है कि वर्तमान में देश भर में कपास की दैनिक आवक वर्ष के इस समय के दौरान दो लाख गांठ की तुलना में 1.5 लाख गांठ (170 किलोग्राम प्रत्येक) है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि, किसान यह सुनिश्चित करने के लिए पीछे हट रहे हैं कि उन्हें अच्छी कीमत मिले। गुजरात कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक, पश्चिमी राज्य में कपास की गांठों का दबाव नवंबर और दिसंबर के दौरान एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में कम था।

एसोसिएशन के मुताबिक, इस साल आवक उम्मीद से कम रही है, हालांकि वे मांग को पूरा करने में सक्षम हैं। हालांकि, स्पिनिंग मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है और उन्होंने घबराहट में खरीदारी से परहेज किया है। अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) भारतीय रिपोर्ट में कहा है कि इस सीजन (अक्टूबर 2021–सितंबर 2022) की आवक 19 प्रतिशत कम 134.8 लाख गांठ थी, हालांकि वे पिछले तीन साल के औसत से मेल खाती है। इक्रा में कॉरपोरेट सेक्टर रेटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि, स्पिनिंग कंपनियों ने पिछले सीजन से कम कीमत पर स्टॉक खरीदा था और चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान मुनाफे के मामले में उन्हें फायदा हुआ। गुजरात के जिनर्स राज्य के भीतर डिलीवरी के लिए 75,500–76,000 रुपए प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) और दक्षिण में मिलों को डिलीवरी के लिए 76,000–76,500 रुपए पर ऑफर किया गया था।

महाराष्ट्र जिनर्स ने गुजरात दरों की तुलना में 1,000 रुपए प्रति कैंडी अधिक बोली। दक्षिण के लिए कीमतें अधिक हैं क्योंकि भुगतान में आमतौर पर देरी होती है।

एमसीएक्स पर दरों के साथ–साथ वापस खींचने के साथ कीमतों में 76,000 रुपए भाव पहुंचने के बाद कीमतों में गिरावट आई थी। फरवरी में डिलीवरी के लिए कपास की कीमत 36,760 रुपए प्रति गांठ (78,925 रुपए प्रति कैंडी) थी। इस सीजन में घरेलू कपास की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं क्योंकि वैश्विक कीमतें मजबूत मांग और तंग आपूर्ति के कारण 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।

इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क में मार्च में डिलीवरी के लिए कपास, वर्तमान में 121.59 यूएस सेंट प्रति पाउंड (74,250 रुपए प्रति कैंडी) पर ऑफर किया गया है। यूएसडीए के मुताबिक, कपास किसानों को मौजूदा स्तर से कीमतों में 20–30 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

भारतीय कपास प्रीमियम पर चल रहा है क्योंकि कुछ बहुराष्ट्रीय व्यापारिक फर्मों ने यूरोपीय वायदा में अपने जोखिम को कम कर दिया है। बेमौसम बारिश से घरेलू फसल के प्रभावित होने की आशंका से भी कीमतों में तेजी आई है।

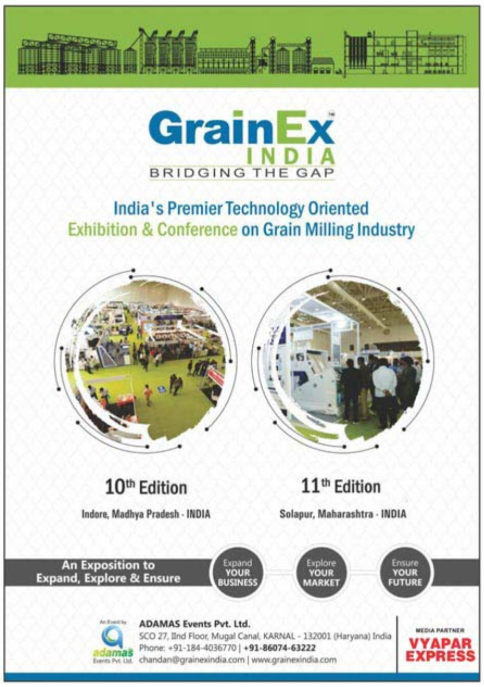

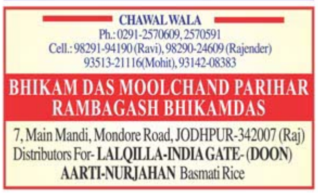

अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मिला भरपूर बजट

कोरोना महामारी की तगड़ी मार के बाद पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा जोर अर्थव्यवस्था को इसकी चोट से 'पूरी तरह और तेजी से उबारने' पर रहा। मगर उनका यह आशावाद और कोशिश बजट के आंकड़ों में नजर नहीं आए। दुनिया भर में मुद्रास्फीति के माहौल और 8 फीसदी से अधिक वास्तविक वृद्धि के आर्थिक समीक्षा के अनुमान के बावजूद 2022–23 में 11.1 फीसदी की नॉमिनल वृद्धि का अनुमान यही बताता है। चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा (जीडीपी) सकल घरेलू उत्पाद के 6.9 फीसदी के बराबर बताया गया है, जो कर राजस्व में बढ़ोतरी के बावजूद 6.8 फीसदी के अपने लक्ष्य से पीछे रह गया।

वित्त मंत्री ने 2025–26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 तक समेटने का संकल्प किया है और अगले साल इसे 6.4 फीसदी पर रखने का उनका लक्ष्य है। मगर खजाने को मजबूत करने का रास्ता ब्याज के बढ़ते बोझ के कारण मुश्किल होगा। 2022–23 में ब्याज भुगतान चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान से 16 फीसदी बढ़ गया है और 2020–21 की तुलना में यह पूरे 38 फीसदी ज्यादा है। कुल व्यय का 23.8 फीसदी ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। सरकार ने लघु बचत कोष पर अपनी निर्भरता कम करने का फैसला किया है और उसे 2022–23 में बाजार से 11.6 लाख करोड़ रुपये की शुद्घ उधारी की उम्मीद है। हालांकि उसकी यह उम्मीद बॉन्ड बाजार को पसंद नहीं आई।

भारतीय सरकारी बॉन्डों को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करने में मददगार कर सुधारों के बगैर ही उधारी का लक्ष्य इतना अधिक रखने के कारण 10 साल के सरकारी बॉन्ड की प्राप्ति उछल गई। बजट में दूसरे अनुमान पुरानी लकीर पर ही दिखे। केंद्र सरकार के शुद्घ कर राजस्व में केवल 9.5 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है और विनिवेश से भी केवल 65,000 रुपये मिलने की उम्मीद बजट में जताई गई है। इसी तरह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से होने वाली आय भी घटने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का नाम लिया मगर यह स्पष्ट नहीं है कि उससे होने वाली आय को ऊपर बताई गई प्राप्तियों में शामिल किया गया है या नहीं। सीतारमण ने राजस्व व्यय की लगाम भी कसकर रखी। ब्याज भुगतान और पूंजीगत संपत्तियां तैयार करने के लिए मिलने वाले अनुदानों को अलग रखकर 2022–23 के लिए राजस्व के मद में व्यय को 2021–22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में पूरे 29 फीसदी कम कर दिया गया।

कोविड के कारण दिए जा रहे समर्थन में कुछ कमी का अनुमान तो पहले ही था। उर्वरक, पेट्रोलियम और खाद्य पर मिलने वाली सब्सिडी में 26 फीसदी से अधिक कमी का अनुमान लगाया गया है और मनरेगा पर खर्च में भी इतनी ही कमी का अनुमान है। व्यय के नए कार्यक्रम भी बहुत कम हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यय में इस कमी और अनुमान से कम राजकोषीय संकुचन से मिली रकम का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय बढ़ाने में किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा, जो 2019–20 की तुलना में 2. 2 गुना अधिक है। जाहिर है कि बजट का पूरा जोर महामारी से उबारने के लिए कल्याणकारी उपायों के बजाय बुनियादी ढांचे और उभरते हुए क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश पर है। वर्ष 2022–23 के आम बजट का आर्थिक मॉडल एकदम साफ है: सार्वजनिक निवेश में लगातार बढ़ोतरी से निजी निवेश भी जुटेगा और वृद्घि का पहिया दौडने लगेगा।

परिवहन पर खर्च और अन्य पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी यही सोचकर की गई है, हालांकि उनमें से कुछ लक्ष्य बहुत महत्त्वाकांक्षी प्रतीत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री ने अगले साल 25,000 किलोमीटर लंबाई के नए राजमार्ग बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए रोजाना 68 किलोमीटर लंबे राजमार्ग बनाने होंगे। लेकिन आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष की पहली छमाही में रफ्तार केवल 20.9 किलोमीटर प्रतिदिन रहने की बात कही गई है। बुनियादी ढांचा सृजन पर बजट का जोर कृषि सिंचाई योजना, ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण पेयजल मिशन में आवंटन वृद्घि में भी नजर आया। मगर शहरीकरण पर भी सरकार का पूरा जोर रहा।

वित्त मंत्री चाहती हैं कि भारत के शहरों को सभी के लिए अवसर के साथ सतत निवास का केंद्र बनाया जाए। इसके लिए अमृत मिशन पर जोर दिया जा रहा है और सार्वजनिक परिवहन में निवेश बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कर के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने आयात के बजाय आत्मनिर्भर बनने की बात एक बार फिर कही। कर में कई तरह के बदलावों को देसी उद्योग की संरक्षा के लिए जरूरी बताया गया है। प्रत्यक्ष कर में क्रिप्टो कर के अलावा कुछ बदलाव किए गए।

कराधान को आसान और नरम बनाने की बात कही गई और नई विनिर्माण इकाइयों एवं स्टार्टअप को कर प्रोत्साहन दिए गए। मगर मध्य वर्ग और वेतनभोगियों के लिए बजट में अलग से कुछ भी नहीं था। उन्हें आयकर में किसी तरह की राहत नहीं दी गई। न तो कर छूट की सीमा बढ़ाई गई, न आयकर स्लैब बदले गए और न ही निवेश के जरिये नई तरह की छूट दी गई।

Worldwide - Different People, Different Tastes, One Chioce :
DUNAR
Basmati Rice
Also Buy Online at : www.buybasmatiriceonline.in

Leading Canvassing Agent in Ahmedabad
Specialist in Basmati Rice
D.J. BROKER'S
Canvassing Agent for Basmati Rice, Wheat & All Grains
12/2, Kabutar Khana, Sindhi Market, Chokha Bazar, Kalupur, Ahmedabad-380001
Email: dhaneshk735@gmail.com
Contact : +91-9426834991, 9898349911 (Dhaneshbhai)

भारत का गेहं निर्यात पहुंच सकता है 65-70 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर

दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रों के देशों की अच्छी मांग के कारण भारत का गेहं निर्यात चालू वित्त वर्ष में 65–70 लाख टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। ओलम एग्रो इंडिया के उपाध्यिक्ष का कहना है कि हमने दिसंबर तक 45 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। हम हर महीने 5–6 लाख टन गेहूं का निर्यात कर रहे हैं और इससे 15–20 लाख टन अतिरिक्त शिपमेंट की संभावना है। निर्यात 65–70 लाख टन हो सकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल–नवंबर अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 41.1 लाख टन था, जिसका मूल्य 8,547.58 करोड़ रुपए था। इसकी तुलना में, पिछले वित्त वर्ष में कुल गेहूं का निर्यात केवल 20.8 लाख टन था, जिसका मूल्य 4,033.81 करोड़ रुपए था। वर्ष 2012–13 में, भारत ने 65.1 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, जिससे 10,529 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 2013–14 में 55.7 लाख टन गेहूं का निर्यात किया और 9,277.65 करोड़ रुपए मिले। इस महीने की शुरुआत में, अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने भारत का चालू वित्त वर्ष में भारत गेहूं के निर्यात का अनुमान बढ़ाकर 65 लाख टन कर दिया। भारत इस क्षेत्र में श्रीलंका, फिलीपींस, बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात कर रहा है।

भारतीय गेहूं की कीमत वर्तमान में 300–305 डॉलर प्रति टन है। दिसंबर में गेहूं का निर्यात मूल्य 320 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया था। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल (आईजीसी) के मुताबिक, अर्जेंटीना वर्तमान में अपने गेहूं की अपस्ट्रीम रिवर डिलीवरी के लिए 304 डॉलर प्रति टन की बोली लगा रहा है, जबकि फ्रांस अपने ग्रेड गेहूं के लिए 324 डॉलर पर ऑफर दे रहा है। यूएस का सॉफ्ट रेड विंटर व्हीट 347 डॉलर और हार्ड रेड विंटर व्हीट 397 डॉलर प्रति टन पर चल रहा है। आईजीसी गेहूं सब–इंडैक्सह 295 पर साल–दर–साल 28 प्रतिशत ऊपर है। सूत्रों के अनुसार, भारत को जो फायदा होता है, वह यह है कि ऑस्ट्रेलिया मार्च तक ओवरसोल्ड रहता है और इस क्षेत्र के किसी भी देश को इस अवधि के दौरान गेहूं खरीदना हो तो, उन्हें केवल भारत आना होगा। ऑस्ट्रेलिया में इस समय रसद समस्याएं हैं क्योंकि वह जहाजों के मुख्यधारा के नेविगेशन मार्ग पर नहीं है। जहाजों को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मुख्य लाइन से अलग जाना पड़ता है।

भारत के मामले में, अगर जहाज अफ्रीका या दक्षिण–पूर्व एशिया में गेहूं ले जाते हैं, तो वे खनिज या कोयला या ऐसी कोई भी वस्तु ले कर वापस आ सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के मामले में नहीं है। यह एक कारण है कि भारत इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड गेहूं निर्यात कर सकता है, जबकि रूस–यूक्रेन संघर्ष के तेज होने से भी भारतीय गेहूं निर्यात बढ़ने में मदद मिल सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में क्षेत्र में शिपिंग शुल्क भी बढ़ जाएगा। मार्च के बाद भारत को एक और फायदा यह होगा कि गेहूं की नई फसल बाजार में आएगी।

इस कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही के अंत से पहले किसी अन्य देश का गेहूं नहीं आएगा। इसलिए, भारत तब तक गेहूं का एकमात्र स्रोत होगा।

EVEREST
RICE MILL ELEVATOR BUCKET
Quality, Reliability & Maximum Volume Capacity Of Your Plants Always Insist On...
Product Range : From 3" to 20", Mild Steel, Stainless Steel & Plastic Buckets
Manufacturers: V.L. INDUSTRIAL WORKS
Opp. Railway Station, VANGAON-401103 • Tel : 02528-244025/285/654 Fax : 02528-244122
Mob : 9225147630, 9765351833 Email : sales@everestelevatorbuckets.co.in
Website : www.elevatorbucket.in

NAGRAJ
GRAIN TRADING CO.
Wholesaler & Distributor of
Wheat, Tuvar Dal and Rice
GF/4, Krishna Apartments, Chhotalal Cross Road, Odhav, Ahmedabad-382415 • Tel.: 079-22972211
9428117879 Tarun Kumavat

Raj Singh Barka
Sale Purchase of Boilers:- Rice Plant Steam Engine, Drier etc. On Commission Basis
Contractors: All Kind of Heavy Loading, Unloading Dismentals Eractions, Mfrs. & Fabricators M.S. Pipe, Storage Tanks Chimney, Cyclone, I.D.Fans, on Labour Rates.
Works: 3, Meerut Road Opp. Neher Colony Mandir, KARNAL
Resi.: 127, Gali No.3, Opp. Sector-6, Green Belt, Karan Vihar, KARNAL-132001
Tel.: (R) 0184-2250536 M: 9812031874, 9017708899

Mob. 94170-28517
99149-28517
Paramjit 'S' Pamma
Deals in: Old Rice Plant, Old Paddy Drier, Old Colour Sortex, Old Solvent Plant, Old Sella Plant, Chakki Plant, Boiler, Ice Plant & Any Other Sick Unit
H. No.517 St. No.2 Near Bobby Mahant Mandir Kular Nagar, MOGA-142001 (Pb.) Email: pammji69@gmail.com

RICE Merchants & Commission Agent
BANSHIDHAR SATYANARAYAN
Ch.8, Surajpole Mandi, JAIPUR
Mobile:. 9571813688

बृजेश कुमार अग्रवाल
श्री गणेश एन्टरप्राईजेज
कमीशन एजेन्ट
धान–1121–बासमती–शरबती–गेहूं और जौ आदि के कमीशन एजेन्ट
बी–9, नवीन गल्ला मण्डी दादरी–203207 (गौतमबुद्ध नगर) उ० प्र०
Ph.: 0120-2665680 • Mob.: 94120-62917, 93120-68780

AMBER TRADING COMPANY
Rice Merchants & Commission Agents
E-3, New Anaj Mandi, Surajpole, JAIPUR (Raj.)
Email : ambertradingco@yahoo.com
Organised By :- Mr. SATPAL
Distributors :- Dunnar, Basmati Rice
Ph. (O): 0141-2640343, 6543932 (R) 27203051
Mobile : 09314503881

Authorised Distributor's of KRBL Ltd. Products
INDIA GATE BASMATI RICE
ROYAL FOOD PRODUCTS
18-V, Strotten Muthiah Mudali Street, Sowcarpet, CHENNAI-79
Mob : Tejraj Kothari-9840055850, Pankaj Kothari-98406 60000
Tel : 25360794, 25392283, 25392757 Email : pankaj.kothari@gmail.com

MAHADEV CANVASSING AGENT
RICE, WHEAT, GRAIN CANVASSING AGENT
Ph.: 079-65212545, 39828466
Mob. : 98251-09226
178/1, Kabutarkhana Sindhi Comm. Market, AHMEDABAD-380002

बिहार ने धान खरीद में तोड़ा पिछला रिकॉर्ड

बिहार में उसना चावल मिलों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही अरवा चावल मिलों को उसना में कन्वर्ट करने को लेकर सरकार प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।

विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री को बताया गया कि चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरु की गई है। किसानों को समय पर उनकी धान पैदावार का भुगतान किया जा रहा है।

सहकारिता विभाग की सचिव का कहना है कि, लक्ष्य के अनुरुप सभी जिलों से धान का क्रय किया जा रहा है। सहकारिता विभाग के मुताबिक, 61 हजार मीट्रिक टन की रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति की गई है।

प्राेक्याेरमें‍ट पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू की गई है, इसके माध्यम से 35 हजार किसानों द्वारा अब तक 2.63 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की गई है। धान अधिप्राप्ति के लिए 15 फरवरी, 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।

बिहार मे पैक्स के धान अधिप्राप्ति की शुरुआत

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री का कहना है कि, हम लोगों ने अपने यहां सबसे पहले पैक्स के धान अधिप्राप्ति की शुरुआत करवायी, इससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। अब तक साढ़े चार लाख किसानों से 32.61 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति होचुकी है।

उनका कहना है कि, इस वर्ष 15 फरवरी तक धान अधिप्राप्ति की समय सीमा निर्धारित की गई है, इच्छुक किसान समय सीमा में इसका लाभ उठाएं। बैठक में सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि किसानों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए निरंतर निगरानी और अनुश्रवण करते रहें। साथ ही लक्ष्य के अनुरुप धान अधिप्राप्ति को लेकर तेजी से काम करें।

धान अधिप्राप्ति का भुगतान किसानों को समय पर करते रहें जिससे उन्हें इसका लाभ मिले। उनका कहना है कि, सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिये पूरी तरह तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उसना चावल की खपत अधिक है। इसको लेकर उसना चावल के मिलों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। अरवा चावल मिलर्स को उसना मिल में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करें।

MURLI MANOHAR TRADERS
Canvassing Agents For:
RICE PULSES GRAINS
82/1, Sindhi Commercial Mkt. Kalupur, AHMEDABAD-2
Ph.: 079-22122053, 22122003, 22123383
Fax: 22123379 Resi.: 22821183, 22823003
Mobile: 98250-64720 (Vikesh)
98240-11682 (Dilip), 98250-64720 (Manu)
98240-76740 (Thakur)

Always Use World's Finest
Him-anchal's Basmati Rice
SKBR EXPORT PVT. LTD.
Plot No. 181/21, Industrial Area, Phase 1, CHANDIGARH-160019
+91-9915102077 (Naresh Goel)
E: himanchalbasmati@gmail.com
Website : www.skfrice.com

P LILADHAR & CO.
Rice Canvassing Agents
103, Vyapar Bhawan, Ist Floor, A.P.M.C. Market-II, Phase-II, Vashi, Navi MUMBAI-400703
Tel.: (O): 022-27837665, 27838345, 27838109
(R) 022-25643710, 25681927 Telefax: 022-67907905
Mob: Paresh: 9821222369, 9323943710
Nitin: 9820010201, 9320310201 Jitu: 9323981927
E-mail: p_liladhar@hotmail.com

Aggarwal Canvassing Agent
Deals in: Rice, Paddy, Broken all kinds of Basmati & Non Basmati Rice
12, New Janta Market, Near Novelty Cinema, KARNAL-132001
M: 9215550377, 9466571277 Sunil Garg
M: 9034055567 Anil Garg
Email: sunilgarg2585.sg@gmail.com

Deepak Ohri (Prop.)
Rice Brokers
M:. 9814066221 9781368000
GANPATI TRADING COMPANY
Shop No.2, Old Hariana Adda, Gaushala Bazar, HOSHIARPUR-146001
Tel.: (O) 01882-233103, 243103, 520103, 520203 (R) 01882-227193
Branch Office: Ganapati Trading Co.
Silver Plaza, Opp. Sanjog Palace Sodal Road, JALANDHAR CITY
Ph.: 0181-2293030 Mobile: Rahul Ohri (Monty) 9914020037, Jyoti Parkash Ohri 9814866221

Raj Canvassing Agent
Rice, Pulses, Rice Bran, Grain Brokers
22, Dhan Mandi, UDAIPUR-313001
Tel. : (O) 0294-2523056, 2414056
(R) 0294-2485056 Mob.: 9414155956

RICE & PULSES SPECIALIST
HISARIA BROTHERS
CANVASSING AGENTS OF PULSES, BASMATI RICE
79, Acharappan Street, CHENNAI-600001
Tel. (O) 25226188, 25224132 (R) 26426320, 26423414
Fax : 25221139 Mob. : 98410-26188
Cable: 'DALKING' Email : goyals@vsnl.com

स्थापित 1960
भारत वर्ष में बिल्टीकट दलाली की पहली विश्वसनीय
You Grow With
Dalal Surajbhan Khandelwal & Co.
45/1, Sindhi Commercial Market, Kalupur, AHMEDABAD-380002
Ph.off: 079-22121809, 22122335, 22124380, 22123539, 22158251, 22166621 Fax: 079-22120414 Resi.: 26401346 (Rakesh), 26461009 (Nipun R.) 26614623 (Umesh), 26610227 (Vivek U.)
Mobile:. 98240-12216 (V.K.) 98240-61878 (R.K.), 98240-32451 (U.K.), 98243-12122(Nipun)
Other Concers: UNITY CANVASSER (Rice Division)
RAGHUPATI TRADERS (Pulses Division)
नोट : हमारी अन्य कोई सम्बन्धित नाम से कोई फर्म नहीं है।

Rice Basmati Specialist
Ph.: 0184-2255365 Resi. 2280185 (O.P.) 2
Fax: 2255365 M.: 9416034365
G. N. ENTERPRISES
Canvassing Inspecting & Packing Agents of All Types of Rice & Seeds
101, Janta Grain Market, KARNAL
Other Concern- Om Prakash & Co.

खाद्य तेलों की कीमतों में लगेगी लगाम

घरेलू बाजार में पिछले काफी अर्से से खाद्य तेलों की कीमतों में भारी उछाल रखा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से खाद्य तेलों की कीमत थामने को लेकर खाद्य तेल आयात की निर्भरता कम करने के लिए नीतिगत कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत तिलहन फसलों को बढावा देने के लिए आम बजट में एक नए मिशन की शुरूआत करने का प्रस्ताव किया है। जिसके माध्यम से अगले पांच वर्ष में तिलहन उपज 50 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

इस तिलहन मिशन से खाद्य तेल आयात की निर्भरता कम होने में मदद मिलेगी। जिससे न सिर्फ घरेलू बाजार खाद्य तेलों की बढती तेजी कम हो जाएगी बल्कि तिलहन फसल को बढावा मिलने से किसानों को भी काफी फायदा होगा। दरअसल खाद्य तेल की वैश्विक कीमतें घरेलू कीमतों को प्रभावित करती रही है। केंद्र सरकार की तरफ से बाजार के साथ–साथ किसानों का ध्यान रखते हुए आम बजट में विशेष प्रावधान किया है। जिसको लेकर आम बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को दिए गए अनुदानों में इसका उल्लेख किया गया है।

केंद्र सरकार की तरफ से खाद्य तेल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन की उपज एवं उत्पादकता बढाने के लिए एक नया मिशन एनएमई–ओएस शुरु करने का निर्णय लिया है। अगले पांच वर्षों में तिलहन मिशन के जरिए 1676 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता के साथ 54.10 मिलियन टन की तिलहन उपज पैदा करना है।

बासमती चावल के निर्यात में सुधार की संभावना

बासमती निर्यात ठीक होने की संभावना है क्योंकि ईरान, सऊदी अरब अपनी खरीद बढ़ा सकते हैं। जबकि, बासमती के निर्यात में अक्टूबर में नई फसल आने के बाद से लगातार तीन महीनों तक शिपमेंट में गिरावट रही है। लेकिन अब इसमें सुधार की संभावना है।

इसके अलावा, यूक्रेन में भू–राजनीतिक तनाव से शिपमेंट को बढ़ावा मिलने के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार, निर्यातकों ने शिपमेंट के लिए लगभग 2.5 लाख टन के कांट्रैक्टा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि पिछले साल जनवरी के पूरे महीने में किए गए वॉल्यूम का 70 प्रतिशत है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि, रमज़ान 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 21 मार्च से नवरोज। जैसा कि सऊदी अरब और ईरान इन उत्सव की मांगों के लिए जनवरी–फरवरी के दौरान खरीद करते हैं, हमें अच्छे ऑर्डर की उम्मीद है।

भले ही शिपमेंट इन दो महीनों में पिछले साल पहले के स्तर से मेल खाता हो, फिर भी हम पिछले बैकलॉग को जारी रखेंगे। इसलिए एसा नहीं लगता कि 2021–22 के दौरान 44 लाख टन का लक्ष्य हासिल होगा। सीजन 2021–22 (अप्रैल–नवंबर) में बासमती शिपमेंट एक साल पहले की तुलना में 21 प्रतिशत से घटकर 24 लाख टन रह गया। अप्रैल–नवंबर 2020 के दौरान उच्च कारोबारी गतिविधियों के बावजूद, कुल बासमती चावल के शिपमेंट में 2020–21 के वित्तीय वर्ष के दौरान 46.3 लाख टन के साथ चार प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई। आधिकारिक डेटा के मुताबिक, ईरान और कुवैत को छोड़कर, सऊदी अरब, इराक, यमन, यूएई, यूएस, यूके, कतर और ओमान जैसे अन्य सभी प्रमुख गंतव्यों में बासमती निर्यात में वृद्धि हुई है।

ईरान ने 2020 में आयात में कटौती की थी क्योंकि उसके पास पिछले वर्ष से अच्छी घरेलू फसल के साथ–साथ आगे का स्टॉक था। लेकिन 2021 में इसकी खरीद में सुधार हुआ जबकि दूसरे देशों से गिरावट आई। अप्रैल–नवंबर 2021–22 के दौरान, ईरान को बासमती निर्यात एक साल पहले की अवधि से तीन प्रतिशत बढ़कर 5.1 लाख टन पहुंच गया। सूत्रों के अनुसार, दिसंबर 2021 में, निर्यात सौदों के पंजीकरण से पता चलता है कि मात्रा में पांच प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वास्तविक शिपमेंट में 15–20 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है क्योंकि कुछ निर्यातक कीमतों में बढ़ोतरी के बाद खरीदारों के साथ फिर से बातचीत कर रहे हैं। नवंबर 2021 में, कांट्रैक्टी पंजीकरण में पांच प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि वास्तविक शिपमेंट एक साल पहले की अवधि की तुलना में 21.4 प्रतिशत घटकर 2,38,121 टन रह गया।

> **ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि, रमज़ान 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 21 मार्च से नवरोज। जैसा कि सऊदी अरब और ईरान इन उत्सव की मांगों के लिए जनवरी-फरवरी के दौरान खरीद करते हैं, हमें अच्छे ऑर्डर की उम्मीद है।**

सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में, बासमती की कीमतें अक्टूबर 2021 में 890–900 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 980–990 डॉलर पहुंच गई हैं, जबकि अक्टूबर 2020 में कीमतें लगभग 970 डॉलर प्रति टन थी जो दिसंबर 2020 में घटकर लगभग 830 डॉलर प्रति टन रही थी।

रबी फसलों की बुआई बढ़कर 689.14 लाख हेक्टेयर

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, चालू रबी में दलहन की प्रमुख फसल चना के साथ ही तिलहन की फसल सरसों की बुआई में बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के अनुसार, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को हल्का नुकसान तो हुआ है, लेकिन आगे मौसम अनुकूल रहा तो इनके उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय के मुताबिक, 28 जनवरी 2021 तक रबी फसलों की बुआई बढ़कर 689.14 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई 680.77 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। मंत्रालय के मुताबिक, तिलहनी फसलों की बुआई चालू रबी में बढ़कर 102.04 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई 83.19 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

रबी तिलहन की प्रमुख फसल सरसों की बुआई चालू रबी में बढ़कर 91.44 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुआई 73.12 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

अन्य तिलहनी फसलों में सनफ्लवर की बुआई 1.17 लाख हेक्टेयर में, मूंगफली की 4.89 लाख हेक्टेयर में और सफ्लावर की 74 हजार हेक्टेयर के अलावा केस्टर सीड की बुआई 2.92 लाख हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई क्रमशः 1.06 लाख हेक्टेयर में, 4.81 लाख हेक्टेयर में, 58 हजार हेक्टेयर और 2.79 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। दालों की बुआई चालू रबी में थोड़ी बढ़कर 166.43 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अविध इनकी बुआई 164.85 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

रबी दलहन की प्रमुख फसल चना की बुआई चालू रबी में बढ़कर 114.27 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इसकी बुआई 110.03 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। मसूर की बुआई चालू रबी में 17.64 लाख हजार हेक्टेयर में, मटर की 10.14 लाख हेक्टेयर में और उड़द की 7.61 हेक्टेयर में हुई है। पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इनकी बुआई क्रमशः 16.91 लाख हेक्टेयर में, 10.36 लाख हेक्टेयर में और 7.95 लाख हेक्टेयर में हुई थी। मूंग की बुआई चालू रबी में 4.77 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले रबी की समान अवधि में इसकी बुआई 6.61 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। मोटे अनाजों की बुआई चालू रबी में 50.14 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के 51.97 लाख हेक्टेयर से कम है।

मोटे अनाजों में ज्वार की बुआई चालू रबी में 24.38 लाख हेक्टेयर में और मक्का की 18.37 लाख हेक्टेयर में तथा जौ की बुआई 6.78 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इनकी बुआई क्रमशः 27.38 लाख हेक्टेयर में, 17.02 लाख हेक्टेयर में और 6.87 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई चालू रबी में घटकर 342.37 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के 345.86 लाख हेक्टेयर से कम है। धान की रोपाई चालू रबी में घटकर 28.16 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इसकी रोपाई 34.90 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी।

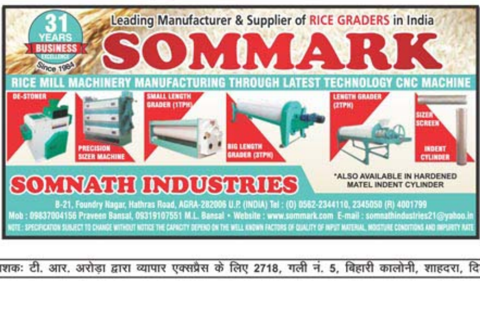

स्वामी, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशकः टी. आर. अरोड़ा द्वारा व्यापार एक्सप्रैस के लिए 2718, गली नं. 5, बिहारी कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032 से प्रकाशित तथा बालाजी आफसैट उल्धनपुर 1/11884, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 से मुद्रित। संपादक-टी. आर. अरोड़ा

4.jpg